आर.एन.आई नं. : HP-HIN/1999/3010

पोस्टल रजि. नं. SOLAN/96

निष्पक्ष, निर्भीक व बुलंद साप्ताहिक

हिमाचल वार्ता

E-paper : himachalvarta.com

Email: himachalvarta@gmail.com

वर्ष : 19 अंक : 46 | 27 सितंबर से 3 अक्तूबर, 2018 | मूल्य : 2 रुपया | वार्षिक : 100 रुपए

संरक्षक
ईश्वरचंद गुप्ता एडवोकेट
संपादक
राजेश राही
फोन नं. 094180-96004
मोबाइल नं. 098570-14001
सलाहकार
एस.पी. जैरथ
मोबाइल नं. 094182-27701

25 मेगावॉट से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए : मुख्यमंत्री

हिमाचल प्रदेश में सौर तथा जल विद्युत क्षेत्रों में निवेश के लिए निवेशकों का स्वागत

हिमाचलवार्ता समाचार सेवा

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गत दिवस ग्रेटर नोएडा में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित द्वितीय वैश्विक पुनर्निवेश नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक मीट एवं प्रदर्शनी में भाग लिया।

मुख्यमंत्री के पूर्णकालिक अधिवेशन में बोलते हुए जय राम ठाकुर ने निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत और सौर ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करने का स्वागत किया, क्योंकि राज्य उद्यमी अनुकूल है और ऊर्जा क्षेत्र के विकास में भागीदार बनने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल विद्युत की अपार क्षमता है और सत्ता में आने के तुरन्त बाद राज्य सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र को पर्यटन में शामिल करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि राज्य के जल विद्युत जलाश्यों को जल विद्युत पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख उद्यमी अनुकूल उपायों पर चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि परियोजना आवंटित करते समय अग्रिम प्रीमियम की दर को 20 लाख रुपये से घटाकर महज एक लाख रुपये प्रति मेगावॉट किया गया है और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भूमि पट्टे की दर एक रुपया प्रति वर्ग मीटर से भी कम है। उन्होंने कहा कि पहले से ही बिजली पैदा कर रही परियोजनाओं के अलावा आवंटित परियोजनाओं से राज्य सरकार की प्रारंभिक 12

वर्षों के लिए रॉयल्टी को स्थगित कर दिया गया है और यह अगले 28 वर्षों के दौरान प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में आवंटित परियोजनाओं के मामले में अनुबन्ध अवधि के दौरान 12 प्रतिशत नि:शुल्क बिजली समान रूप से एकत्र की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली बेचने के सम्बन्ध में बिजली उत्पादकों की मुख्य समस्या का भी समाधान कर लिया है। उन्होंने कहा कि हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड 25 मेगावॉट तक की सभी जल विद्युत परियोजनाओं से एक निश्चित दर पर बिजली खरीदेगा। उन्होंने कहा कि बिजली की दरें जिन्हें अनुबन्ध के क्रियान्वयन की तिथि से निर्धारित किया जाता था, को अब वाणिज्यिक संचालन की तिथि से तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार समस्त जल विद्युत परियोजनाओं को नवीनीकरण ऊर्जा की श्रेणी में शामिल करने के मुददे को उठाती रही है ताकि इन्हें भी नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं को दिए जा रहे लाभ मिल सके, क्योंकि वर्तमान में 25 मेगावॉट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को इस श्रेणी के अन्तर्गत शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजनाएं हरित ऊर्जा का उत्पादन करती है, जो पर्यावरण अनुकूल है। उन्होंने कहा कि यदि यह मांग मान ली जाती है तो राज्य में और अधिक निवेशक आकर्षित होंगे जिससे आर्थिकी और मजबूत होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी बढ़ावा देने की इच्छुक है और स्पिति क्षेत्र में पहले ही 1000 मेगावॉट सोलर पार्कों की पहचान की जा चुकी है और निकट भविष्य में 200 मेगावॉट क्षमता की विभिन्न परियोजनाएं भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य की नाजुक पारिस्थितिकी को देखते हुए सौर ऊर्जा नीति तैयार की गई है और सरकार केवल हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और वर्तमान में 90 प्रतिशत उपयोग की गई ऊर्जा स्वच्छ है। उन्होंने कहा कि राज्य ने थर्मल पॉवर हाउस की स्थापना पर भी प्रतिबन्ध लगाया है।

उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 27000 मेगावॉट जल विद्युत के दोहन की क्षमता है, जो समूचे देश का एक-चौथाई है, जिसमें से 10547 मेगावॉट का 151 परियोजनाओं के माध्यम से दोहन किया जा चुका है। इसके अलावा, 2395 मेगावॉट क्षमता की 63 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, 8000 मेगावॉट क्षमता की 770 परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है, जबकि 2100 मेगावॉट की बड़ी परियोजनाओं का शीघ्र आवंटन किया जाएगा। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने इण्डिया एक्सपो मार्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊर्जा निदेशालय द्वारा स्थापित हिमाचल पैविलियन का उद्घाटन किया।

ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी, प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे।

निवेशक राज्य के प्राकृतिक उत्पादों को उच्च दरों पर खरीदने को तैयार : राज्यपाल

हिमाचलवार्ता समाचार सेवा

शिमला। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि देश के प्रमुख कृषि निवेशक राज्य के समूचे प्राकृतिक उत्पादों को डेढ़ गुणा अधिक मूल्य पर खरीदने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, शीघ्र ही प्राकृतिक खेती राज्य के रूप में उभर कर सामने आएंगे।

राज्यपाल कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित छः दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक परियोजना के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है कि जो किसान प्राकृतिक खेती को प्रदर्शित करेगा उसे मास्टर प्रशिक्षक बनाया जाएगा और इससे दूसरे किसान भी प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को राज्य सरकार के माध्यम से रियायती मूल्य पर भारतीय नस्ल की गाय प्रदान की जाएंगी जिसके लिए निजी उद्यमियों ने लागत को 50 प्रतिशत वहन करने की इच्छा जताई है। किसानों को गायों को उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।

राज्यपाल ने शून्य लागत प्राकृतिक खेती की धारणा को विकसित करने में पद्मश्री सुभाष पालेकर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वह वर्तमान समय के सन्त है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसान समुदाय के लिए समर्पित कर दिया और अपने अनुसंधान के माध्यम से उन्होंने समूचे विश्व की सहायता की। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं की ही प्रेरणा से उन्होंने स्वयं खेती के इस तरीके को अपनाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कृषि भूमि अन्य प्रदेशों से अधिक उपजाऊ है तथा प्राकृतिक खेती के तहत 'जीवामृत' और 'गांजीवामृत' का उपयोग कर ज़मीन सोना उगलेगी।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि किसानों को रासायनिक खेती में कोई रूचि नहीं है, क्योंकि यह ज़हरीली है और वे जैविक खेती को भी नही अपना रहे है, क्योंकि यह महंगी होने के साथ-साथ भरोसेमंद भी नहीं है। अब प्राकृतिक खेती एकमात्र विकल्प है, क्योंकि इसमें किसानों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता और अनेक लाभ हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को अपनाकर हम राष्ट्रीय हित में मानवता से जुड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं।

उन्होंने प्राकृतिक खेती पर विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के तथ्यों तथा परिणामों के आधार पर प्राकृतिक खेती के विभिन्न लाभों का विवरण दिया। उन्होंने वैज्ञानिकों से प्राकृतिक खेती पर अनुसंधान तथा इसका परिणाम देने का आग्रह किया ताकि सच्चाई प्रत्येक के समक्ष आ सके।

पद्मश्री सुभाष पालेकर, शून्य लागत प्राकृतिक खेती के परियोजना निदेशक राकेश कंवर, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रो. अशोक सरयाल, कृषि निदेशक डॉ. देश राज शर्मा, पुलिस अधीक्षक कांगड़ा सन्तोष पटियाल, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा छः जिलों के किसान इस अवसर पर उपस्थित थे।

आईटीआई बडौन में राष्ट्रीय पोषण शिविर का आयोजन किया गया

हिमाचलवार्ता समाचार सेवा

रेणुका जी। आईटीआई बडौन में राष्ट्रीय पोषण महा विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इसमें आईटीआई स्टाफ व छात्र शामिल हुए। इस अवसर पर अपने व्याख्यान में वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ शरद चंद्र त्रिवेदी ने कुपोषण व एनीमिया

खून की कमी से होने वाली शारीरिक मानसिक परेशानियों के बारे में बताया व इन्हें दूर करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति किस हद तक कारगर है इसकी भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खाने-पीने के मामले में सावधानी जरूरी है इसको लेकर हर व्यक्ति बच्चा बूढ़ा जवान सबको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए तथा अच्छी आदतें अपनानी चाहिए ताकि शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहे और और हर व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी का शिकार होने से बच सकें। उन्होंने कहा कि कुपोषण यानी शारीरिक कमजोरी से अधिकतर रोग होते हैं भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें पौष्टिक तत्व भरपूर हो और धूप का सेवन भी जरूरी है इससे एनीमिया से बचाव होता है। डॉक्टर त्रिवेदी ने छात्रों को नशाखोरी की बुराइयों से भी अवगत कराया और उनसे इस सामाजिक बुराई के खिलाफ जमकर संघर्ष करने व स्वयं भी मादक द्रव्य से परहेज रखने का आह्वान किया।